प्रेस विज्ञप्ति

14 नवंबर, 2016

रणदीप सिंह सुरजेवाला, इंचार्ज कम्युनिकेशंस, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निम्नलिखित बयान जारी किया :–

'बिना सोचे समझे किए नोट बदलने के' एक फैसले ने देश के 125 करोड़ लोगों को एक बिन बुलाई आफत में धकेल दिया है।

देश की तरक्की का पहिया जाम है और करोड़ों लोग अपना काम छोड़ लाईनों में धक्के खा रहे हैं और वो भी खुद का पैसा निकलवाने के लिए। बगैर तैयारी, बगैर सोच व झूठी वाहवाही बटोरने के लिए किए गए मोदी सरकार के इस नासमझ फैसले से आम जनता पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा है।

ऐसा नहीं है कि लोगों के पास पैसे नहीं हैं। हैं तो, मगर देश के ताकतवर तानाशाह प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने रातोंरात लोगों के गाढ़े कमाई के पैसों को कागज के टुकड़ों में तब्दील कर एक **'आर्थिक अराजकता'** का माहौल देश पर थोप दिया है। मोदी जी यह मान बैठे हैं कि बड़े बहुमत की जीत उन्हें सब मनमानियों को अधिकार देती है। परंतु प्रजातंत्र में सत्ता के अधिकार मनमाने नहीं, जन–माने होते हैं।

मोदी जी, देश न जुमलों से चलेगा न ढकोसलों से। न मजाक उड़ाने से, न आंखे दिखाने से। न रोने धोने से, न छटपटाने से। देश के 125 करोड़ व्यथित, पीड़ित, दुखी एवं परेशान लोगों की ओर से हम मोदी सरकार से जवाब मांगते हैं :–

1. **बैंकों के बाहर लाईन में खड़े लोग न चोर हैं और न उनके पास काला धन है।**

   कोई बेटी की शादी के लिए पैसे चाहता है।

   किसी का बेटा इलाज के बगैर दम तोड़ रहा है।

   कोई बूढ़ी मां दवाई के लिए पैसे की चाहत में छः घंटे लाईन में खड़ी बेहोश हो गई।

   कई करोड़ो महिलाओं के पास पैसा होते हुए भी राशन के लिए पैसा नहीं।

   मजदूर मेहनत के पैसे के लिए ठोकरें खा रहा है, और किसान फसल बोने के लिए भटक रहा है।

   बताईये, इनमें से कौन चोर है और किसके पास काला धन है? मोदी जी, आपने तो पूरे देश को अपराधी बना दिया।

   क्या प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी उन परिवारों से घर–घर जाकर माफी मांगेंगे, जिन्होंने आपकी 'आर्थिक अराजकता' के चलते अपनी जान गंवा दी या फिर सबकुछ गंवा दिया? उदाहरण हज़ारों–लाखों हैं, पर 23 निर्दोष व्यक्तियों की सूची संलग्न है।

2. कालाधन तो असल में आपके सूट–बूट वाले चंद दोस्तों के पास है, जो लाईन में खड़े ही नहीं।

क्या कारण है कि आपका कोई बड़ा उद्योगपति दोस्त, आपके अफसर, बीजेपी के आपके मंत्री, आपके मुख्यमंत्री, आपके नेता– बैंकों की लाईन में खड़े ही नहीं, जबकि पूरा देश खड़ा है? क्या यह नहीं बताता, कि काला धन असली में है कहां?

क्या कारण है कि नोट बदलने के फैसले के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के कोलकाता स्थित मात्र एक खाते नंबर 554510034 में अकेले 08 नवंबर को 500/1000 रु. के नोटों में एक करोड़ रु. जमा करवाया गया। खाते की एक कॉपी संलग्न है। **मोदी जी, भाजपा के राष्ट्रीय व प्रांतीय सभी बैंक खातों की मार्च से सितंबर, 2016 की बैंक डिटेल्स जारी करने की हिम्मत दिखाएं। दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा कि नोट बदलने के फैसले से पहले कितना पैसा बदला गया?**

3. **तथ्य व आंकड़े दिखाते हैं कि नोट बदलने के मोदी सरकार के फैसले की जानकारी पहले से ही चुनिंदा लोगों को थी।**

   अकेले सितंबर, 2016 में अगस्त, 2016 के मुकाबले देश के बैंकों में 5,88,600 लाख करोड़ रुपया अधिक जमा करवाया गया। (RBI के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई, 2016 में सभी बैंकों में 96,196 बिलियन रुपया जमा हुआ और सितंबर, 2016 में यह राशि बढ़कर, 1,02,082 बिलियन रुपया हो गई)। जमा होने वाले रुपये की यह अप्रत्याशित बढ़ोत्तरी अपने आप में काले धन की कहानी बयां करती है।

   अगर RBI के जुलाई से सितंबर के बीच जमा होने वाले पैसे के साल, 2015 व 2016 के आंकड़ों को देखा जाए, तो भी काले धन को खातों में जमा करने की कहानी उभरकर आती है। जुलाई, 2015 में सभी बैंकों में लगभग 88,301 बिलियन रुपया जमा हुआ। सितंबर, 2015 में जमा होने वाली राशि 89,462 बिलियन रुपया थी। यानि लगभग 1 लाख करोड़ रुपया अतिरिक्त जमा हुआ। परंतु जुलाई, 2016 में जमा होने वाली राशि, 96,196 बिलियन रुपया थी और सितंबर, 2016 में जमा होने वाली राशि 1,02,082 बिलियन रुपया थी, यानि 14 लाख करोड़ अधिक। एक साल में अप्रत्याशित तौर से बढ़े केवल इन्हीं आंकड़ों से काले धन की सच्चाई का चेहरा सामने आता है।

4. नोट बदलने के फैसले से पहले ही मोदी जी ने देश से धन बाहर भेजने की सीमा 130 प्रतिशत तक बढ़ा दी थी। 26 मई, 2014 से पहले, प्रतिवर्ष हर देशवासी केवल 75000 अमेरिकी डॉलर बाहर भेज सकता था। सत्ता में आते ही, मोदी जी ने 3 जून, 2014 को इसे 75000 डॉलर प्रतिवर्ष से 1,25,000अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष बढ़ाया। फिर सत्ता का एक साल पूरा होते ही 26 मई, 2015 को इसे बढ़ाकर, अमेरिकी डॉलर 2,50,000 प्रतिवर्ष कर दिया। आरबीआई का निर्देश संलग्न है।

   नतीजा यह हुआ कि प्रतिवर्ष बाहर जाने वाला पैसा 10,400 करोड़ रु. से बढ़कर साल 2015–16 में 30,000 करोड़ रु. या 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। क्या मोदी जी बताएंगे कि प्रतिवर्ष 75000 डॉलर से 2.5 लाख डॉलर की छूट देकर वो देश का पैसा विदेश भेजने में किसकी मदद कर रहे थे?

5. प्रधानमंत्री बार बार यह दम भरते हैं कि उनकी सरकार ने 1,25,000 करोड़ रुपया Income Tax Survey व Voluntary income disclosure scheme से जुटाया है।

   हम मोदी जी को याद दिलवाना चाहेंगे कि यूपीए की कांग्रेस सरकार ने मात्र दो साल यानि 2012–13 व 2013–14 में सिर्फ Income Tax survey व Assessment से

1,30,800 करोड़ रुपया जुटा दिया था। Voluntary Income disclosure scheme, जो 1997 में आई थी, उससे भी तत्कालीन सरकार ने 33,695 करोड़ रुपया जुटाया था, जो आज के रुपये की कीमत के मुताबिक 85,153 करोड़ रुपया बनता है। यह मोदी जी द्वारा इकट्ठे किए गए 65,250 करोड़ रु. से काफी अधिक है। परंतु इतिहास गवाह है कि ऐसी स्कीमों से कभी भी अर्थव्यवस्था में काले धन की मात्रा नहीं घट पाई।

6. आपने संकट से निपटने का 50 दिन का समय मांगा है, पर देशवासी पूछ रहे हैं कि यह संकट पैदा किसने किया?

I- क्यों पर्याप्त मात्रा में नए नोट छापकर बैंकों को नहीं दिए?

II- क्यों ATM मशीनों के Hardware व Software को पहले से ठीक नहीं किया गया?

III- जेटली जी कहते हैं कि नए नोट पहुंचने और एटीएम चलने में 3 से 4 हफ्ते लगेंगे। तो 4 हफ्ते देश के लोगों का क्या होगा?

IV- क्यों Income Tax व दूसरे विभाग, व्यापारी और दुकानदार पर Tax terrorism फैला रहे हैं?

V- 2000 रु. का नोट चलाने से कालाधन बढ़ेगा या फिर घटेगा?

VI- क्या जन–धन के खातों का इस्तेमाल कालाधन को सफेद करने के लिए नहीं किया जा रहा?

VII- नए नोटों में कोई नया Security Feature नहीं है। न कोई नया वॉटरमार्क है, न Security thread, न Fiber और न Latent Image। ऐसे में मात्र रंग व साईज़ बदलने से क्या नए नोटों की पर्याप्त सुरक्षा रह पाएगी? क्या मोदी जी इसकी जिम्मेदारी लेते हैं?

VIII- पुराने नोटों को नए नोटों से बदलने की कुल लागत क्या है? क्या यह लागत 25,000–30,000 करोड़ रुपया है, जैसा कई अर्थशास्त्रियों ने कहा है?

IX- क्या मोदी सरकार ने नोट बदलने के संकट से उत्पन्न हुए करोड़ों लोगों के नष्ट हुए समय व राष्ट्रीय उत्पादकता में कमी की कीमत आंकी है?

देश इन सब सवालों का जवाब चाहता है।

7. 2014 के चुनाव से पहले आपने विदेशों से 80 लाख करोड़ रु. कालाधन 100 दिन में लाने और 15 लाख सबके खाते में जमा कराने का वायदा किया था। लगभग 1000 दिन बीतने के बाद ये एक जुमला बन गया।

अब 50 दिन में संकट खत्म करने का नया जुमला दे दिया।

मोदी जी, देश जुमलों से नहीं, जिम्मेदारी निभाने से चलेगा।

यह देश स्कीम भिड़ाने से नहीं, शासन चलाने से बढ़ेगा।

गरीबों की आंखों में धूल झोंकना बंद कीजिए और सरकार चलाना शुरू कीजिए।